नियंत्रित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ कुछ आधुनिक परियोजनाएं हैं। बोर्ड न केवल कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा बल्कि प्रदूषण नियन्त्रण हेतु और मानकों को क्रियान्वित करने के लिए नई योजनाएं बनाकर तकनीकी और सलाहकारी सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। उद्योग से एक निश्चित उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण जानकारी और उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। प्रदूषण मानकों के समयावधि के अन्दर प्रदूषण पर नियन्त्रण करने के लिए शीघ्र और प्रभावी उपाय करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्रियान्वयन की आदर्श योजनाएं सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार की जाएंगी। अमर ऐसा कर दिया जाएगा तो इससे उद्योग के विकास और प्रदूषण नियन्त्रण में मदद मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

4·20 म० प०

प्रधान मंत्री द्वारा अपनी विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद के पिछले सत्र से अब तक अपनी विदेश यात्राओं के परिणामों से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

वेंकूवर में राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय प्रधान मंत्री नाकासोने के साथ विचार-विमर्श करने के लिए मैं 12 अक्तूबर को थोड़ी देर के लिए टोकिया में रुका था। हमने आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। उन्होंने 20 करोड़ डालर के बराबर राशि का एक आसान और बिना शर्त के जापानी ऋण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान भारत-श्रीलंका समझौते का समर्थन करता है।

राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन 13-17 अक्तूबर को वेंकूवर में सम्पन्न हुआ।

वेंकूवर शिखर सम्मेलन बढ़ते हुए इस तरह के अनुमानों के बीच आरम्भ हुआ कि राष्ट्रमण्डल दक्षिणी अफ्रीका में जातीय पृथग्वासन के विरुद्ध अपने अभियान में पीछे रह गया है। यह बात गलत साबित हुई। ब्रिटेन को छोड़कर राष्ट्रमण्डल के सभी देश इस बात के प्रति सहमत थे कि प्रतिबन्धों का इच्छित प्रभाव पड़ना शुरू हो गया हैं। अत: हमने दबाव को और तेज करने और प्रतिबधों के क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया.। हमने राष्ट्रमण्डल के प्रतिबन्धों से संबंधित कार्यक्रम को व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिलाने और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए काम करने की प्रतिज्ञा ली।

अनेक नए सुझाव, जिनमें हमारे सुझाव भी शामिल थे, स्वीकार किए गए। हम निरन्तरता के आधार पर प्रतिबंधों के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर सहमत हुए। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि इन प्रतिबन्धों को निष्क्रिय करने के किसी भी प्रयास का पता लगाया जाए और उसे प्रकाश में लाया जाए। इस बात पर सहमत हुए कि फ्रेटोरिया जातीय पृथग्वासनवादी शासन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली के साथ फेटोरिया के संबंधों के निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ अध्ययन दल की आश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। भावी स्थिति के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे जिसमें और अधिक प्रतिबंध लगाए जाने भी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबन्धों से

संबंधित कार्रवाई कार्यक्रम को केवल ब्रिटेन को छोड़कर राष्ट्रमण्डल के अन्य सभी देशों में स्वीकार किया है।

हम सबने अफ्रीकी राज्यों को राष्ट्रमण्डल की सहायता के समन्वय का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मोजाम्बिक को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष दोष की स्थापना प्रदान की गई। पृथकवासन के शिकार और विरोधियों को दी जाने वाली राष्ट्रमण्डल की सहायता में वृद्धि की जाएगी। हम इस बात के लिए सहमत हुए कि दक्षिण अफ्रीका में सेन्सरशिप हटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को उच्च प्राथमिकता दी जाए क्योंकि यह ऐसी सेन्सरशिप है जो दुनिया के लोगों से दक्षिणी अफ्रीका के बारे में सच्चाई को छुपाती है। इन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए तेज गति और मार्ग-निर्देशन देने के लिए शिखर सम्मेलन ने विदेश मंत्रियों की एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता कनाडा द्वारा की जाएगी और इसमें भारत को शामिल किया गया है।

वेंकूवर में फिजी की घटनाओं की प्रमुख रूप से चर्चा हुई। अधिवेशन के उद्घाटन वक्तव्य में मैंने उस देश में हाल में घटी घटनाओं के कारणों में निहित जातीय स्वरूप और लोकतंत्र को कम महत्व दिए जाने के बारे में अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की। फिजी राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं रहा। शिखर-सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रमण्डल में फिजी के पुनः प्रवेश पर तभी विचार किया जाएगा जबकि परिस्थितियों को देखते हुए इसकी आवश्यकता समझी जाए। साथ ही इस संदर्भ में इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि इस पुनः प्रवेश का आधार उन बुनियादी सिद्धान्तों के अनुरूप हो जो इस संगठन के दिशा-निर्देश रहे हैं। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि राष्ट्रमण्डल फिजी की समस्याओं के निराकरण में सहयोग करने के लिए सदा तत्पर रहेगा।

वेंकूवर में जारी गई राष्ट्रमण्डल विज्ञप्ति में भारत-श्रीलंका समझौते का जोरदार समर्थन किया गया है। इस समझौते को सर्वोच्च राजनेतृत्व की कार्रवाई कहा गया है।

शिखर-सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी विश्व व्यापार पर वेंकूवर घोषणा, जिसके अन्तर्गत सभी महाद्वीपों के विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर इकट्ठा करने की व्यवस्था है। इस घोषणा में विश्व में बढ़ते हुए संरक्षणवाद की प्रथा के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की गई है और संरक्षणवादी उपायों के "स्टैण्ड स्टिल" और "रोक बैक" पर पुण्टा-डेल-एस्टे वचनबद्धताओं को पूरा सम्मान दिए जाने की मांग की गई है। इस घोषणा में यह स्वीकार किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों की स्थिति अलाभकारी है और इस असमानता को देखते हुए उरुग्वे व्यापार वार्ता में इनके हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमने सुदूर शिक्षा अर्थात ज्ञान को अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिकांश लोगों तक पहुंचाने के लिए नई संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को संवर्धित करने के लिए राष्ट्रमण्डल कार्यक्रम शुरू किया। भारत इस पहल में और इससे लाभ उठाने में भी पर्याप्त रूप से सक्षम है।

राष्ट्रमण्डल में प्रतिनिधित्व प्राप्त प्रभुसत्ता सम्पन्न सरकारों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों की परिधि में वेंकूवर शिखर सम्मेलन में हुई सहमतियों में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस संगठन की सक्रियता और उपयोगिता की पुष्टि की गई। प्रतिबंधों के सवाल पर एक विपरीत मत की चिन्ता न करते हुए इस शिखर सम्मेलन ने विश्व में शांति और स्थिरता के मुख्य मसलों के बारे में विश्व मत के अधिकांश भाग को एक साथ मिला दिया। कनाडा की सरकार ने इस सम्मेलन के लिए जिस उल्लेखनीय सावधानी के साथ प्रबंध किए उनकी मैं सराहना करना चाहूंगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने में प्रधान मंत्री,

ब्रियान मुल्लारोनी ने जो महत्वपूर्ण और कल्याणपूर्ण भूमिका निभाई है उसकी भी मैं सराहना करना चाहूंगा।

वेंकूवर में जब मैंने प्रधानमंत्री मुल्रोनी के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया, उस समय मैंने कई अन्य नेताओं के साथ भी बातचीत की जिनमें बंगलादेश, गुयाना, माल्दीव, तंजानिया और जाम्बिया के राष्ट्रपति, ब्रूनी के सुल्तान और आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, माल्टा, न्यूजीलैन्ड, सिंगापुर और जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री और नाइजीरिया के प्रतिनिधिमण्डल के नेता शामिल थे।

18 अक्तूबर को मैंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भारत और लोकतंत्र विषय पर जोदीदी स्मारक भाषण दिया।

अगले दिन मैंने नार्वे की प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रो हार्लेन ब्रेटलैण्ड के नेतृत्व में स्थापित आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में हिस्सा लिया। इस बहस में डेनमार्क, नार्वे तथा जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था।

मैंने विदेश नीति एसोसिएशन, एशिया सोसाइटी तथा भारतीय वाणिज्य चैम्बर की एक संयुक्त बैठक में अपनी विदेश नीति तथा देशी की स्थिति पर भी एक भाषण दिया।

मैंने राष्ट्रपति रीगन के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका की संक्षिप्त यात्रा की। हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे दोनों देशों के बीच निरन्तर बातचीत एक-दूसरे देश की बेहतर समझबूझ और पारस्परिक लाभप्रद सहयोग को विस्तृत करने के लिए अनिवार्य है।

मैंने कांग्रेस के नेताओं के साथ सुबह का नाश्ता लिया जिनमें हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष और सीनेट में बहुमत के नेता भी शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप अब अमरीका में नाभिकीय अस्त्रों के लिए पाकिस्तान की अनथक चाह की गंभीरता को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा रहा है।

राष्ट्रपति रीगन और मैंने क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में व्यापक और लाभप्रद विचार-विनिमय किया। अमरीका ने भारत-श्रीलंका समझौते को अपना पूर्ण समर्थन देने की पुन: पुष्टि की। मैंने पाकिस्तान के अस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम पर अपने देश की गहरी चिन्ता को पुन: दोहराया।

हमारे विचार-विमर्शों में आज के अन्य महत्वपूर्ण मसले शामिल थे। मैंने लघु और मध्यम दूरी के नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ और अमरीका के बीच करार की संभावना का स्वागत किया।

हमने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया। मेरी 1985 की यात्रा के दौरान तैयार की गई कार्य-सूची अधिकांश पूरी हो गई है और एक नई कार्य-सूची अब तैयार की गई है। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक पेशकदमी को 1988 तक तीन वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए जिसके ठोस परिणाम सामने आए हैं। हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी इस सहयोग का विस्तार करने का निश्चय किया।

सागर विज्ञान विकास, जल-प्रबंध और शुष्क क्षेत्र में कृषि के क्षेत्रों में मिलकर अनुसंधान करने की परियोजनाएं भी तैयार की गई हैं। दोनों देशों के विशिष्ट हित के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए

प्रमुख अमरीकी संस्थाओं में हमारे वैज्ञानिकों को नौकरी दिलाने के लिए विकास शिक्षावृत्तियां प्रारम्भ की जा रही हैं।

हम व्यापार और निवेश में अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए। हम औषधि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अपना कार्य विस्तृत करेंगे। हम संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अपने संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। हम रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम दोनों देशों के विधायकों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाने के महत्व पर सहमति हुई।

दिल्ली लौटते हुए मैं एम्सर्टडम हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री लुब्बर्स से मिला। बंगलौर में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन के बाद सदन को दिए गए वक्तव्य में मैंने यह कहा था कि भारत की अध्यक्षता के दौरान हम क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत और व्यापक करने का प्रयास करेंगे।

2 से 4 नवम्बर तक मैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के तीसरे शिखर सम्मेलन के लिए काठमांडू में था जिसकी ओर अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

बंगलौर में हमने एक-दूसरे के लोगों के बीच निकटतर सम्पर्क स्थापित करने के बारे में पांच नए विचार प्रस्तुत किए थे। हमने क्षेत्रीय सहयोग को अधिक सार्थक तत्व प्रदान करने की दिशा में भी कई कदम उठाए। हमने यह भी निश्चय किया कि विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया जाए जो आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने की एक रूप रेखा तैयार करे। हमने "सार्क" सुरक्षा खाद्य भण्डार के ऊपर भी बातचीत की। हमने औषधि के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार को रोकने, भीषण दुर्घटना प्रबंधन, वानिकी और पारिस्थितिकी तथा व्यापार, उद्योग, मुद्रा और वित्त जैसे नए क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने के बारे में विचार-विमर्श किया। हम क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना के संबंध के समान सिद्धांत, समान प्रक्रिया एवं नियम तैयार करने पर भी सहमत हुए। और अन्त में हमने सार्क सचिवालय को कार्यात्मक बनाने की दिशा में भी काम करने का निश्चय किया।

मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हम अपने इन लक्ष्यों को पूरा कर सके हैं और इस तरह हमने अपने दायित्वों का निर्वाह किया है।

हमारी अध्यक्षता की अवधि में करीब-करीब 100 आयोजन हुए यानी हफ्ते लगभग दो। इनमें से 45 तो भारत ही में आयोजित किए गए।

बंगलौर में जिन नए विचारों पर सहमति हुई थी उन सबको अब परियोजनाओं का रूप दे दिया गया है। काठमांडू शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के सीधे प्रदर्शन के साथ ही "सार्क" दृश्य-श्रव्य आदान-प्रदान का शुभारम्भ हुआ। शिक्षा वर्ष 1988 से "सार्क" शिक्षावृत्ति, पीठ स्थापना और छात्रवृत्ति का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।

काठमांडू में "सार्क" सुरक्षित खाद्यान्न भंडार की स्थापना की गई। यह पहला मौका है जब इस क्षेत्र के देशों ने आपातकालीन परिस्थितियों में अपने संसाधनों को इस तरह एक करने का निश्चय किया है।

आतंकवाद का दमन करने से संबद्ध "सार्क" के क्षेत्रीय अभिसमय पर भी इसी शिखर सम्मेलन के हस्ताक्षर किए गए। इसके लिए मंच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में सार्क देशों के विशेषज्ञों की बैठक में ही तैयार हो गया था और उन्होंने ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध तय किए थे जो आतंकवादी हों लेकिन

जिनका स्वरूप राजनीतिक न हो । यह अभिसमय अपने आप में इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे हमारे क्षेत्र के सभी देशों की यह इच्छा प्रकट होती है कि वे आतंकवाद के खतरे का मुकाबला कैसे किया जाए।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : पाकिस्तान में भी हममें शामिल है ?

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : हमारे इस क्षेत्र में सूखा, बाढ़ और समुद्री तूफान की पुनरावृत्तियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई । भीषण दुर्घटना के सिलसिले में राहत प्रबंध को दक्षिण एशियाई सहयोग की परिधि में लाने की दिशा में हमारी पहलकदमी पर, काठमांडू में हम लोग इस बात पर सहमत हुए कि अपने क्षेत्र में पर्यावरण के अनुरक्षण और परिरक्षण का अध्ययन करने के लिए और प्राकृतिक आपदाओं के कारणों और परिणामों का भी अध्ययन करने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाए ।

भारत का यह विश्वास है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को और आगे बढ़ाकर व्यापार, उद्योग, मुद्रा तथा वित्त के अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को अपनी परिधि में शामिल करना चाहिए। इस विचार को धीरे-धीरे स्वीकृति मिल रही है । काठमांडू में हमने यह निश्चय किया कि इन दिशाओं में अध्ययन करवाएंगे। हमें उम्मीद है कि इन अध्ययनों से इस क्षेत्र के देशों को इन दिशाओं में सहकारी उद्यमों की ओर अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मि[illegible]हनत कर [illegible]र सम्मेलन के दौरान मैं "सार्क" सचिवालय भी गया और वहां लोगों को काम करते देखा। यह [illegible]हनीय बात है कि अपनी स्थापना के बाद एक वर्ष के भीतर-भीतर यह सचिवालय बहुत अच्छी तरह काम करने लगा है और अपने दायित्व को पूरी तरह निभाने की दिशा में अग्रसर है ।

काठमांडू शिखर सम्मेलन के दौरान मुझे उपस्थित नेताओं के साथ द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर अनौपचारिक विचार-विमर्श करने का मौका मिला ।

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं नेपाल के महामहिम की सरकार की इस बात के लिए सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने इस सम्मेलन का बहुत ही बढ़िया इन्तजाम किया। इस शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय बहुत हद तक हमारे अध्यक्ष नेपाल के के महामहिम महाराजाधिराज के विशिष्ट नेतृत्व को जाता है !

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा की तरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

— —

4.35 म० प०

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रेणुपद दास बोल सकते हैं ।